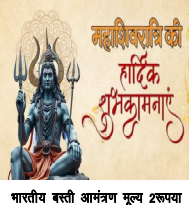




दैनिक

भारतीय बस्ती



R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं B.S.T 59 बस्ती, वर्ष 47 अंक 205 रविवार 15 फरवरी 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या-फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ 4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

समाजसेवी हरिकेशव धर द्विवेदी के निधन पर शोक



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। इंदिरा चैरिटेबल सोसाइटी के दो दशकों से अध्यक्ष रहे डॉ. हरिकेशवर धर द्विवेदी का लंबी बीमारी के बाद जलियावली को 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

डा. हरिकेशवर धर द्विवेदी की श्रद्धायात्रा के दौरान संस्था के केंद्रीय कार्यवाहक कलांगनज के पिकोरी सनी पर उन्हें पुष्प अर्पित किया गया। संस्था के सौंदर्यो अजय कुमार पाण्डेय की अनुमति पर संस्था के पदाधिकारीगण और शुभेच्छुओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। डा. हरिकेशवर धर द्विवेदी ने अपने जीवन में समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी अख्यता में संस्था ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी की और समाज के विकास में अपना योगदान दिया।

समाधान दिवस में 4 मामले निस्तारित



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। फरवरी मास के दूसरे शनिवार को कलवारी थाने में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थानाध्यक्ष कलवारी गजेन्द्र प्रताप सिंह ने थाना परिसर में क्षेत्र से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सभी चौकी प्रभारी, बीपीओ, हल्का प्रभारी और राजस्व कर्मी उपस्थित रहे।

थानाध्यक्ष ने सुनवाई के बाद हल्का लेखापाल और बीपीओ को पापना पत्रों पर विधिक कार्रवाई कर उनका निस्तारण करने का निर्देश दिया। थाना समाधान दिवस में कुल 24 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से सभी राजस्व विभाग से संबंधित थे। इन 24 प्रार्थना पत्रों में से 4 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष 20 प्रार्थना पत्रों को निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

पेड़ से लटका मिला युवक का शव

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। हरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बसेवा राय में शनिवार सुबह हड़कपे मध गया। गांव के पुरुष विस्तार तालाब किनारे एक जामुन के पेड़ से रस्ती के फंदे से लटकता हुआ एक युवक का शव मिला। युवक की पहचान बसेवा राय निवासी 28 वर्षीय अंकुर उर्फ अकेश पुत्र प्रताप के रूप में हुई है। परिवार में बताया कि अंकुर गांव के काली मंदिर में आयोजित कथा कार्यक्रम में शामिल होने गया था। देर रात तक वह घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने अपने स्तर पर उसकी खोजबीन शुरू की। हालांकि, इस संबंध में थाना स्तर पर कोई सुशुद्धगी दर्ज नहीं कराई गई थी। शनिवार सुबह करीब 9 बजे ग्रामीणों ने तालाब के पास जामुन के पेड़ से युवक को फंदे से लटकता देखा। तलाक इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फिलहाल युवक की मौत के कारणा की स्पष्ट पुष्टि नहीं हो सकी है। आसाराम के लोग शव घटना को पारिवारिक कारण से जोड़कर देख रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और आरोपी शुरु कर दी है और अन्य विधिक कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी है।

यूपी को मिलने वाला है सबसे लम्बा एक्सप्रेसवे

लखनऊ (आभा)। 594 किलोमीटर लम्बे यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के मेन कैरिजवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बाहनों का आवागमन शुरू होने के पहले सुखालोक उपायों पर काम चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित एक्सप्रेसवे के किनारे खम्बे लगा कर लोहे के तारों से फेंसिंग कराई गई है। उत्तर प्रदेश को अब तक का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे जल्द ही मिलने वाला है। शनिवार को इस बारे में कुछ अपडेट्स आईं। यूपी के

भद्रेश्वरनाथ मंदिर परिसर में लगेगा खोया पाया शिविर, एसडीएम ने किया उद्घाटन



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। रविवार को महाशिव रात्रि पर्व की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शनिवार को उप जिलाधिकारी बस्ती सदर शत्रुघ्न पाठक, सीओ बस्ती सदर सत्येन्द्र प्रताप तिवारी और सचिव के संसद डा. वीके वर्मा ने श्री भद्रेश्वरनाथ मंदिर परिसर में समाचार पत्र वितरण कर कार्यक्रम सेवा समिति द्वारा उप प्रकाश गोस्वामी के संयोजन में संचालित बिछड़े मिले, खोया पाया माध्यम शिविर का उद्घाटन किया। कहा कि महाशिवरात्रि पर्व पर लाखों की संख्या में मनकों की आस्था उमड़ती है। ऐसे में उप प्रकाश गोस्वामी द्वारा खोया पाया शिविर संचालन एक अच्छी पहल है, इससे मेले में बिछड़े लोगों को अपनी से मिलाना आसान हो जाता है।

समिति के संसद डा. वीके वर्मा ने कहा कि खोया पाया शिविर की डॉ. राम कृष्ण लाल 'जगमग' को 'राष्ट्रीय साहित्य मणि' पुरस्कार



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। अलीगढ़ महोत्सव में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में विरचित कवि डॉ. राम कृष्ण लाल 'जगमग' को उनके साहित्यिक योगदान के लिए राष्ट्रीय साहित्य मणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पिछले पांच दशक से साहित्य के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय और चर्चा में रहने वाले कवि की दिवंगी कविता 'दिलाल', विद्या खण्ड का कथा, 'हम तो केवल आदमी हैं', सच का दस्तावेज खुलियों की गैरिया बाल सुमन, बाल घेताना, नरें मुन्नी का सासार आदि कृतियों के रचयिता डॉ. जगमग कवि चारों का अब तक छह संस्करण प्रकाशित हो चुका है।

प्रसन्नता व्यक्त करते हुए चिकित्सक एच साहित्यकार डा. वीके



औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नन्दी ने लखनऊ स्थित विकास भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे

बिर्हा गांधिका द्वारा सुश्री मायावती पर अश्रु टिप्पणी से रोष: बसपा नेताओं ने किया गिरफ्तारी की मांग



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। बिर्हा गांधिका प्रतापगढ़ की रुचि यादव द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी सुश्री मायावती के प्रति अपमानजनक गीत गाये जाने से लोगों में रोष है। शनिवार को बसपा के पूर्व मण्डल प्रभारी के पी. राठौर के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने पुलिस अदालत को सम्बोधित ज्ञान सीओ सिटी को सौंपा। मांग किया कि सुश्री मायावती के प्रति अपमानजनक अश्रु टिप्पणी करने वाली गांधिका रुचि यादव, विरह कम्पनी व रचयिता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखकर 15 फरवरी को कार्यवाही और गिरफ्तारी किया जाए जिससे भविष्य में किसी के भी द्वारा ऐसी पुनरावृत्ति

महाशिवरात्रि पर होगा सामूहिक रुद्राभिषेक और 56 भोग प्रसाद



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। रविवार को महाशिवरात्रि पर्व पर श्री कर्णेश्वरनाथ मंदिर परिसर में सुबह 9 बजे से सामूहिक रुद्राभिषेक प्रारंभ होगा। सनतान धर्म वेदना वैरिदेव टाट्ट के अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने आगामी धार्मिक कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। बताया कि महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भगवान भोलेनाथ के पावन एवं पवित्र जल की कणेश्वर मंदिर में सुबह आठवीं व प्रसाद वितरण से जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। 9 बजे से सामूहिक रुद्राभिषेक अनुष्ठान प्रारंभ होगा, रुद्राभिषेक पूर्ण होने पर सभी श्रद्धालुओं

को औद्योगिक विकास प्राधिकरण (पीएचडी) के विकास कार्य, संचालित, निर्माण गति और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के साथ ही अन्य कामों की समीक्षा की। जिसमें मंत्री नन्दी ने निर्माणधीन मेरठ से प्रयागराज तक उत्तर प्रदेश के सबसे लम्बे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में पूछा कि जल्द पूरा कराने और प्रस्तावित सभी नवीन एक्सप्रेसवे का हर हाल में अक्टूबर 2026 तक शिलान्यास कराने के निर्देश दिए।

नौ हो सके। बसपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मण्डल प्रभारी के पी. राठौर ने पत्र देने के बाद कहा कि रुचि यादव को गीतों की अमर प्रस्तुति से बहन सुश्री मायावती की जो अपना आदर्श व मसीहा बनाने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिससे उनमें आक्रोश व्यूत है। प्रशासन मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई ले।

ज्ञान सीटों के दौरान रिक्त बसल, अशफाक अख्तर, मनीष प्रेमी, रविंद्र कर्नाडिया, नागेन्द्र प्रताप 'दीवाना जी', डा. जय सिंह, सदीप कुमार, अकाश सहाय, अभिषेक कुमार, हरि प्रसाद, निहाल, शिमम, प्रवीण कुमार के साथ ही बसपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

के लिए फलाहार प्रसाद की व्यवस्था की गयी है। सायकलान्त भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार व 56 भोग प्रसाद व आरती का आयोजन किया गया है।

राजेश मिश्रा ने बताया कि यह सभी कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए आचार्य एवं प्रकाश त्रिपाठी, सचिव मिश्रा, विद्याल मिश्रा एडवोकेट, सीधम कुमार बोस, विशाल पाण्डेय, अरुण मिश्रा, प्रहिल आरुणमित्र त्रिपाठी के साथ अन्य लोग योगदान दे रहे हैं।

18:टैरिफ बनाम०: आगे कुआं और पीछे खाई-राहुल गांधी

नई दिल्ली (आभा)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी और राष्ट्रपति में सोचने वाली कोई सरकार अमेरिका के साथ ऐसा व्यापार समझौता करती जो कपास किसानों और कपड़ा निर्यात दोनों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करता, लेकिन मोदी सरकार ने इसके विपल्व उलट किया। उन्होंने यह दावा भी किया कि सरकार ने व्यापार समझौते के इन पहलुओं को छिपाया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा, 18 प्रतिशत बनाम शुल्क प्रतिशत शुल्क। झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस बारे में भ्रम फैला रही है। किस तरह से वे भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास उत्पादकों और वस्त्र निर्यातकों को बोझा दे रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि बंगलादेश को अमेरिका में वस्त्र निर्यात पर शुल्क प्रतिशत शुल्क का फायदा दिया जा रहा है, शर्त बने इतनी है कि वे अमेरिकी कपास आयात करें। कांग्रेस

नेता ने कहा, 'भारत के गारमेंट्स पर 18 प्रतिशत शुल्क की घोषणा के बाद जब मैंने संसद में बंगलादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया, तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया कि अगर यही फायदा हमें भी चाहिए तो अमेरिका से कपास मंगानी होगी।' उन्होंने सवाल किया कि अखिर ये बात देश से छुपाई क्यों? कांग्रेस नेता ने कहा, 'ये कैसी नीति है? क्या यह सचमुच में कोई विकल्प है - या फिर आगे कुआं,



पीछे खाई की हालत में फंसने वाला जाल?' उन्होंने कहा कि अगर हम अमेरिकी कपास मंगवाते हैं तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे। अगर नहीं मंगवाते तो हमारा कपड़ा उद्योग पिछड़कर तबाह हो जाएगा। अब बंगलादेश यह संकेत दे रहा है कि वह भारत से कपास आयात की इच्छा रख सकता है। राहुल गांधी ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत में कपड़ा उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ है और करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी इसी पर टिकी है।

मोदी-ट्रम्प ट्रेड डील के विरोध में 'आप' ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

—भारत-अमेरिका डील देश के किसानों के साथ विश्वासघात— डा. राम सुभाष वर्मा

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और बीड प्रान्त के सह प्रभारी पतिराम आजाद ने कहा कि किसानों, एम्प्लॉयमेंट, छोटे व्यापारियों, युवाओं और स्वयं सहाय पर इस ट्रेड डील का गंभीर बात है, जिन्हें वहां लगभग 80 लाख रुपये तक की खसई मिलती है। ऐसे में भारतीय किसान ऐसी कृषि खसई के अभाव में उनसे कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा। सरकार को यह स्पष्टकरण देना ही होगा कि देश के किसान

पर सीधा प्रहार है। इससे छोटे किसानों की आय पर असर पड़ेगा, स्थानीय बाजार विदेशी कर्मियों के हित खोजे जाएंगे और आम जनता पर भारी बोझ बढ़ेगा। यह डील देश हित में नहीं है। राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से जिला। महासचिव होन्ग मान कन्नोजिया, महिला जिलाध्यक्ष मिथलेश भारती, राम सजजन सुर्यवंशी, राधिका की देवी, अद्वुल कयूम, रोशन, बबनू, देवेंद्र के साथ ही आम आदमी पार्टी के अनेक पदाधिकारी शामिल रहे।

भारत का मुसलमान दलितों से बदतर जिन्दगी गुजारने को मजबूर-अकरम अन्सारी



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। शनिवार को मोहिन अन्सार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अन्सारी पूर्वांचल के दो दिवसीय दौरे की समाप्ति में बस्ती पहुंचे। जिलाध्यक्ष समीरकुमार अंसारी के नेतृत्व में कोर्ट परिसर के निकट स्थित कार्यालय पर उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अकरम अन्सारी ने अन्सार सभा के पदाधिकारियों व बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की और कहा कि आज के हालात में मुसलमानों पिछड़ों और सर्वहारा को बेहद जागरूक संगठित और सक्रिय रहना है क्योंकि यह वक्त सियासी समाजी बदलाव का है।

कहा कि आज भारत का मुसलमान दलितों से बदतर जिन्दगी गुजारने को मजबूर है क्योंकि हमने कभी अपने रोजगार तालीम तहफुज की खातिर वोट नहीं किया और न ही खुद सियासत में अपनी विचारणा के साथ सदनों में पहुँचने की कोशिश

की लेकिन पिछले 70 सालों में मुसलमानों ने सेक्स्युरिज्म के नाम पर जिनकी पाठियों को बोट दिया है सोलोन कभी भी मुसलमानों के साथ दो दिवसीय दौरे की समाप्ति में बस्ती पहुंचे। जिलाध्यक्ष समीरकुमार अंसारी के नेतृत्व में कोर्ट परिसर के निकट स्थित कार्यालय पर उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अकरम अन्सारी ने अन्सार सभा के पदाधिकारियों व बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की और कहा कि आज के हालात में मुसलमानों पिछड़ों और सर्वहारा को बेहद जागरूक संगठित और सक्रिय रहना है क्योंकि यह वक्त सियासी समाजी बदलाव का है।

मनरेगा कानून बदले जाने के विरोध में 17 को विधानसभा का घेराव करके मंत्री

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। मनरेगा कानून बदले जाने के सवाल को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन निरन्तर जारी है। शनिवार को कांग्रेस कार्यवाह पर पत्रकारों से बातचीत में कोरिस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि आगामी 17 फरवरी को मनरेगा बचाओ संग्राम की कड़ी में यूपी विधानसभा का घेराव किया जाएगा जिसमें बस्ती के कई संस्था में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यवाही शामिल होंगे। कहा कि भाजपा सरकार भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए गरिमा, सुख और जीवन यापन की गारंटी वाले मनरेगा कानून को कमजोर कर इसे खत्म करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि जबकि मनरेगा को पूरी तरह उसका मूल स्वरूप में बदल नहीं दिया जाता तब तक मनरेगा बचाव की लड़ाई सड़क से



—सड़क से संसद तक जारी रहेगा मनरेगा के लिये संघर्ष— विश्वनाथ चौधरी

लेकर संसद तक जारी रहेगी। बताया कि भारतीय जनता पार्टी के इस मजदूर विरोधी नियम के आते ही कांग्रेस ने 3 जनवरी को ही पूरे देश में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू कर दिया था। पिछले एक महीने

में मनरेगा बचाओ पदचर्या की गई। पत्रकारों के सवालों का उत्तर देते हुए कांग्रेस नेता डा. बाहिर अली सिद्दीकी, शौकत अली नन्दू, सदीप श्रवावर्धन, साहू सुमन आदि, अली अख्तर ने कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम का दूसरा चरण शुरू हो चुका जा रहा है। इसमें हम 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा घेराव करेंगे और राज्य सरकार को बलायों कि कैसे केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ आए पर बोझ डालकर खुद बच जाना चाह रही है। हम यह बतायेंगे कि कैसे मनरेगा कानून में किये जा रहे बदलाव सचमुच दावे को कमजोर करने का एक कुत्सित प्रयास है।

प्रेस ताता में जयन्त चौरी, विनय तिवारी, आरुणिक पाण्डेय, शुभम गांधी आदि मौजूद रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 15 फरवरी 2026 रविवार

सम्पादकीय

कर्ज के दुष्चक्र में उलझा किसान

गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव और खेतीकिसानी में बसती है। लेकिन आजादी के बाद भी कृषि क्षेत्र की विसंगतियां व विरोधाभास अंतिम रूप से दूर नहीं हुए। भले ही किसान दमनकारी साहूकारों के चंगुल से किसी हद तक मुक्त हो गए हों, लेकिन धीरे-धीरे सरकारों, सहकारी और अन्य वित्तीय संस्थानों के कर्ज तल दबते चले गए। फिलहाल सकारात्मक पक्ष यह है कि केंद्र सरकार रिफॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, डिजिटल तकनीकों से खेती के तौर-तरीकों में बदलाव और ऋण विस्तार को आसान बनाने के लिये प्रयत्नशील है। लेकिन नकारात्मक पक्ष यह है कि किसान कर्ज के दुश्चक्र में फंसाता जा रहा है। यह कड़वी सच्चाई हाल रिपोर्ट से प्रकाश में आए आंकड़ों से उजागर हुई है। पिछले दिनों प्रकाशित रिपोर्ट में यह चिंताजनक तथ्य सामने आया है कि अनाज के भंडार के रूप से प्रसिद्ध राज्य पंजाब व हरियाणा के किसान देश के सबसे ज्यादा ऋणग्रस्त राज्यों में शुमार हैं। हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार पंजाब व हरियाणा में प्रति कृषि परिवार पर 2.03 लाख और 1.83 लाख रुपये का ऋण बकाया है। जो देश में सबसे ज्यादा ऋण लेने वाले राज्यों में तीसरा व चौथा स्थान बना है। यह स्थिति तब है जब ऋण का यह राष्ट्रीय औसत 74, 121 रुपये है। केवल आंध्र प्रदेश और केरल में ही इससे अधिक ऋण का बोझ दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि ऋण नगण्य ही है। यह स्थिति भारतीय कृषि में गहरे संरचनात्मक असुतलन को ही उजागर करती है। निस्संदेह, पंजाब और हरियाणा में किसान परिवारों पर भारी कर्ज कोई महज संयोग नहीं है। निर्विवाद रूप से पंजाब व हरियाणा ने देश में हरित क्रांति का नेतृत्व किया है। इन राज्यों ने समय की जरूरत के हिसाब से बहुउत्पयोगी कृषि को अपनाया है और भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ बने हैं। मगर विषम परिस्थितियों के चलते इसका अपेक्षित लाभ किसानों को नहीं मिल पाया।

लेकिन यह एक हकीकत है कि हाल के दशकों में खेती का यह मॉडल काफी दबाव में आ गया है। खेती-किसानी की लगातार बढ़ती लागत, स्थिर कृषि आय, छोटी और खंडित भू-जोत, अनियमित मानसून, खरीद प्रक्रिया में देरी और बढ़ते धेरलू खर्च ने ऋण पर निर्भरता का दुष्प्रभ स्पष्ट कर दिया है। इसमें दो राय नहीं कि देश में संस्थानात्मक ऋण की आसान उपलब्धता ने इन राज्यों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया है। लेकिन यह भी एक कड़वी हकीकत है कि ऋण की सहज उपलब्धता ने किसानों के जीवनयापन के साधन के रूप में उधार लेने की प्रक्रिया को सामान्य स्थिति बना दिया है। किसान खेती-किसानी की जरूरतों से इतर भी बड़े पैमाने पर ऋण लेने लगे। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार दावा करती रही है कि वह किसानों के हितां को हमेशा ही प्राथमिकता देती है। किसानों के जीवन में बदलाव के लिये 84.8 करोड़ किसानों के लिये डिजिटल आईडी, भौगोलिक संदर्भ पर आधारित फसल संवर्धन और सुव्यवस्थित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से दक्षता और पारदर्शिता का वायदा किया जा रहा है। भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना में प्रस्तावित सुधार-फसल चक्र के साथ ऋण की अवधि को संरक्षित करना- इस बात का संकेत है कि ऋण को बदलती कृषि परिस्थितियों के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी और बेहतर ढंग से डिजाइन किए गए ऋण स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ये प्रावधान अकेले ही गहरी जड़ें जमा चुके ऋण संकट की समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं। यह कटु सत्य है कि यदि आय लागत के अनुरूप नहीं बढ़ती, यदि बदलते हालात में फसल विविधीकरण के प्रयास सिर नहीं चढ़ते तथा देश में यदि जलवायु परिवर्तन का चक्र तेज होता है, तो ऋणों का दबाव बना रहेगा। आ चाहे ऋण फिक्की भी कुलतला से संचालित किए जाएं। बेहतरहाल, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे देश के अन्नदाता को ऋण संकट के गंभीर जाल से बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करें।

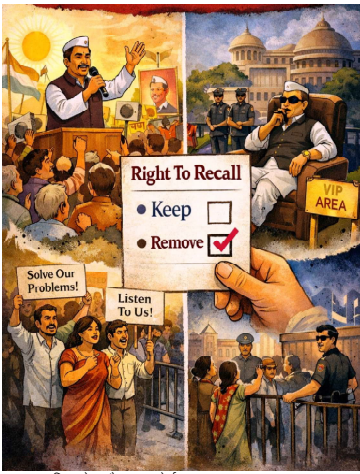
राजनीति: बीच बहस में राइट टू रिकॉल



—डॉ. सत्यवान सौरभ—

लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है और निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के सेवक होते हैं। चुनाव इसी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, जिनके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। किंतु व्यवहार में यह आदर्श अक्सर कमजोर पड़ता दिखाई देता है। चुनाव से पहले नेता जनता के बीच सक्रिय रहते हैं, जनसभाएं करते हैं, समर्याएं सुनते हैं और बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होता है और सत्ता मिलती है, वहीं नेता जनता से दूर होते चले जाते हैं। धीरे-धीरे स्थिति ऐसी बन जाती है कि जनता अपने ही प्रतिनिधियों से मिलने और अपनी बात रखने के लिए संघर्ष करती नजर आती है। यही वह डिग्रेडेशन है जिसने 'राइट टू रिकॉल' जैसे विचार को जन्म दिया है।

वर्मान लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास प्रतिनिधियों को निर्विवाद करने का एकमात्र प्रामाणी साधन अगला चुनाव होता है, जो प्रायः पांच वर्ष बाद आता है। यदि



इस अवधि के दौरान कोई प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, जनता की समस्याओं की अनदेखी करे या अपने चुनावी वादों से पूरी तरह मुकर जाए, तो जनता अस्वस्थ नहीं रहती है। यह असह्यता लोकतंत्र में निराशा और अविश्वास को जन्म देती है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जिस जनता को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, क्या उसे प्रतिनिधि को हटाने का अधिकार भी होना चाहिए?

'राइट टू रिकॉल' इसी प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करता है। इसका तात्पर्य

है कि यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करता, जनता के विश्वास को तोड़ता है या लगातार जनविरोध का प्रतीक बनता है, तो जनता एक निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से उसे कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से हटा सके। यह आगरा लोकतंत्र को केवल प्रतीतिभूत नहीं रहने देती, बल्कि उसे वास्तविक अर्थों में जवाबदेह बनाती है। इससे प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि उनकी जिम्मेदारी

चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे कार्यकाल में जनता के प्रति बनी रहनी है। दुनिया के कई हिस्सों में इस विचार को व्यवहार में लाया गया है। उदाहरणस्वरूप, रिपब्लिकन स्टेट्स में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परंपरा मजबूत बनेगी। इसके अतिरिक्त, यह अधिकार मान्यता है, जहाँ नागरिकों की भूमिका केवल प्रतिनिधि चुनने तक सीमित नहीं रहती। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में स्थानीय स्तर पर रिकॉल चुनावों के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने के व्यवस्था मौजूद है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि 'राइट टू रिकॉल' कोई अव्यावहारिक कल्पना नहीं, बल्कि एक कार्य शील लोकतांत्रिक उपाय है। भारत जैसे विशाल और विविध तापीय लोकतंत्र में जवाबदेही का प्रश्न और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पंचायत स्तर पर कुछ राज्यों में संघर्ष या स्थानीय प्रतिनिधियों को हटाने की सीमित व्यवस्था मौजूद है, किंतु विधायक और सांसद जैसे उच्च पदों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। परिणामस्वरूप, कई बार जनता को पाँच वर्षों तक ऐसे प्रतिनिधियों को झेलना पड़ता है, जो न तो सदन में सक्रिय रहते हैं और न ही अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। भारत में 'राइट टू रिकॉल' की मांग समर्थ-समय पर उठनी चाहिए। इसके समर्थकों का मानना है कि यह व्यवस्था नेताओं में निरंतर जवाबदेही का भाव पैदा करेगी। जब प्रतिनिधि को यह ज्ञात होगा कि

जनता चाहे तो उसे पद से हटा सकती है, तब वह जनहित के मुद्दों को गंभीरता से लेगा। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए, सत्ता के दुुरुपयोग की प्रवृत्ति कम होगी और लोकतंत्र केवल औपचारिक न रहकर जीवंत बनेगा। इसके अतिरिक्त, यह अधिकार मान्यता है, जहाँ नागरिकों की भूमिका केवल प्रतिनिधि चुनने तक सीमित नहीं रहती। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में स्थानीय स्तर पर रिकॉल चुनावों के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने के व्यवस्था मौजूद है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि 'राइट टू रिकॉल' कोई अव्यावहारिक कल्पना नहीं, बल्कि एक कार्य शील लोकतांत्रिक उपाय है। भारत जैसे विशाल और विविध तापीय लोकतंत्र में जवाबदेही का प्रश्न और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पंचायत स्तर पर कुछ राज्यों में संघर्ष या स्थानीय प्रतिनिधियों को हटाने की सीमित व्यवस्था मौजूद है, किंतु विधायक और सांसद जैसे उच्च पदों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। परिणामस्वरूप, कई बार जनता को पाँच वर्षों तक ऐसे प्रतिनिधियों को झेलना पड़ता है, जो न तो सदन में सक्रिय रहते हैं और न ही अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। भारत में 'राइट टू रिकॉल' की मांग समर्थ-समय पर उठनी चाहिए। इसके समर्थकों का मानना है कि यह व्यवस्था नेताओं में निरंतर जवाबदेही का भाव पैदा करेगी। जब प्रतिनिधि को यह ज्ञात होगा कि

लगाई जाए और पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र तथा पारदर्शी संस्थाओं द्वारा संचालित हो, तो दुुरुपयोग की संभावना काफी हद तक कम की जा सकती है। लोकतंत्र कोई स्थिर व्यवस्था नहीं है, यह समय और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होता रहता है। जिस प्रकार सार्वभौमिक मताधिकार, सूचना का अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़े सुधारों ने लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाया, उसी प्रकार 'राइट टू रिकॉल' भी लोकतांत्रिक विकास की अगली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। आज जब जनता पहले से अधिक जागरूक है, सूचना तक उसकी पहुँच व्यापक है और वह अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही है, तब लोकतंत्र में जवाबदेही के नए औजारों की मांग स्वाभाविक है। अंततः 'राइट टू रिकॉल' कोई चमत्कारी समाधान नहीं है, लेकिन यह उस समस्या के अवयव संचालित करता है जिसमें चुनाव के बाद जनता और नेता के बीच दूरी बंद जाती है। यह अवधारणा नेताओं को यह स्मरण करती है कि सत्ता स्थानीय अधिकारों नहीं, बल्कि जनता की अमानत है। यदि इसे संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर, चरणबद्ध और संतुलित रूप में लागू किया जाए, तो यह लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और जम्बूझी बना सकता है। एक सशक्त लोकतंत्र यही होता है। एक सशक्त लोकतंत्र वह होता है जो जनता केवल वाद डालने तक सीमित न रहे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सत्ता को नियंत्रित करने की वास्तविक क्षमता भी रखे।

यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां



—अजय कुमार—

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव 2027 का समय नजदीक आ रहा है, वैकें-वैकें सिपायी हलचल तेज होती जा रही है। इस बार चुनावी रणनीतियों का केंद्र अचानक वहीं जिला बन गया है, जिनसे लंबे समय तक सत्ता के लिहाज से 'अग्रणी' माना जाता रहा। बात हो रही है गौतमबुद्ध नगर यानी नोएडा की। दिल्ली से सटे इस जिले ने अब प्रदेश की राजनीति में वह हंसियत बना ली है, जहां से उठने वाली लहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तकरीबन 100 विधानसभा सीटों को प्रभावित करने की ताकत रखती है। यही वजह है कि भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों ने अपने-अपने मिशन-2027 की शुरुआत यहीं से करने का फैसला किया है। गौतमबुद्ध नगर को आज उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाना लगा है। जिले में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बीते पांच वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बस रही यमुना सिटी, प्रस्तावित फिल्म सिटी और अंतरराष्ट्रीय स्तर का जेवर एयरपोर्ट इस जिले को राज्य की विकास गाथा का गान्धर्व बनाना चुके हैं। राजनीति में विकास अर्थसाधन सबसे बड़ा हथियार होता है और सत्ताचक्र दल इस हथियार को पूरी बार के साथ मैदान में उतारने की तैयारी कर चुका है।

भारतीय जनता पार्टी इस बार विकास के ठोस आर्कडिज़ाइन और बड़ी परियोजनाओं को अपने चुनावी अभियान की रीढ़ बना रही है। 21 फरवरी की यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टर-28 में उत्तर भारत की पहली सोमिकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी



वैष्णव मौजूद रहेंगे, जबकि प्रमाणमंत्री नरेंद्र मोदी वर्षुआ माध्यम से जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 48 एकड़ में लगने वाली इस यूनिट में एचसीएल और फॉक्सकॉर्प जैसी दिग्गज कंपनियां निवेश कर रही हैं। शुरुआती चरण में ही इससे 4,000 प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। भाजपा नेताओं का दावा है कि सोमिकंडक्टर यूनिट केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला कदम है। पार्टी का आकलन है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहले ही आईटी हब के रूप में पहचान बना चुके हैं और अब थिप मैनुफैक्चरिंग के साथ यह इलाका वैश्विक मैन पर और मजबूती से उभरेगा। इसके तुरंत बाद जेवर में बन रहे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुभारंभ की तैयारी है। लगभग 1,334 हेक्टेयर में फैले इस एयरपोर्ट की पहली फेज बमला सालाना 12 करोड़ यात्रियों की है, जिनसे अगले वर्षों में 7 करोड़ तक ले जाने की योजना है। भाजपा इसे पश्चिमी यूपी के विकास का गेमचेंजर मान रही है।

दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने इस बार पुराने अधोविकासों को पीछे छोड़ते हुए नोएडा को ही अपनी सिपायी प्रयोगशाला बनाया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 29 मार्च को दारदी की मिडिओ ब्रिडजिंग कॉलेज से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसे 'समाजवादी समानता भाईवारा रैली' और 'पीडीए भागीदारी यात्रा' का नाम

दिया गया है। सपा नेतृत्व का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में पार्टी के प्रचुर होने से यह साफ कर दिया है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग का गठजोड़ अगर जमीन पर उतर आए तो भाजपा के लिए यह अमान नहीं रहेगी। सपा के रणनीतिकारों का कहना है कि गौतमबुद्ध नगर की सामाजिक संरचना पीडीए फॉर्मूले के लिए अनुकूल है। जिले की करीब 35 प्रतिशत आबादी पिछड़े वर्गों से आती है, जबकि दलित और अल्पसंख्यक जनसंख्या लगभग 30 प्रतिशत बताया है। इसके अलावा गुर्जर, जाट और रंगगी जैसी प्रभावशाली जातियों की मौजूदगी यहां की राजनीति को और दिलचस्प बना देती है। अखिलेश यादव को भरौसा है कि जिस तरह 2012 में उन्होंने यहीं से साइकिल यात्रा शुरू कर पूरे बृहत् नगर हासिल किया था, उसी तरह 2027 में भी नोएडा से उठी लहर लखनऊ तक पहुंचेगी।

बहुजन समाज पार्टी भी इस जिले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। यह जिला बसपा सुप्रीमो मायावती का गृह जनपद है और पार्टी इसे अपनी राजनीतिक शो विंडो मानती है। 15 मार्च को माचवर काशीपुर की जलती पर नोएडा स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में उद्देश्य प्रदर्शन की तैयारी है। पार्टी नेताओं का दावा है कि मेठ, सहायपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ और आगरा मंडल से लाखों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जुटेंगे। बसपा का फोकस साफ है अपने कार्य दलित वोट बैंक को फिर से एकजुट करना और यह संदेश देना कि सत्ता की दौड़ में वह अभी भी

मजबूत खिलाड़ी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गौतमबुद्ध नगर की अहमियत सिर्फ यहां की स्थिति विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं है। नोएडा का राजनीतिक संदेश पूरी दिल्ली-एनसीआर में गुंजाता है। यहां होने वाली रैलियां, घोषणाएं और विकास परियोजनाएं मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए पश्चिमी यूपी के हर जिले तक पहुंचती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस जिले में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार मुकाबला कहीं ज्यादा निकोपीय और कड़ा नजर आ रहा है। जिले में तेजी से बढ़ती शहरी आबादी, रोजगारी मतदाताओं की संख्या और प्रजापति से जुड़े मुद्दे इस बार चुनावी बहस के केंद्र में रहेंगे। नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दस सालों में यहां की आबादी में करीब 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इनमें बड़ी संख्या युवाओं और मध्यम वर्ग के पेशेवरों की है, जिनकी प्राथमिकताएं पारंपरिक जातीय राजनीति से अलग विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हैं। यही कारण है कि 2027 की चुनावी जंग में नोएडा केवल एक जिला नहीं, बल्कि सत्ता की प्रयोगशाला बन चुका है। यहां जो प्रयोग सफल होंगे, वही मॉडल पूरे प्रदेश में दोहराया जाएगा। भाजपा विकास की रफतार और बड़ी परियोजनाओं के सहारे मैदान में है, सपा सामाजिक गठजोड़ और नए संदेश के साथ वापसी की कोशिश में है, जबकि बसपा अपने पुराने आधार को फिर से मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। अभी तक एकल मंडल में होने वाली रैलियां और कार्यक्रम यहां तक कर रहे हैं कि 2027 के चुनावी ऊंट की करवट किस ओर बढ़ेगी, लेकिन इतना सत्य है कि इस बार सत्ता की राह नोएडा होकर ही गुजरेगी।

मुस्लिम वोटों के बंटवारे की चिंता



—संजय सक्सेना—

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाता सदैव निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। उनकी एकजुटता और रणनीतिक वोटिंग ने कई चुनावों के परिणाम बदल दिए हैं। प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब बीस प्रतिशत है, जो सत्ता चार सौ विधानसभा क्षेत्रों में से सवा सौ से अधिक पर अपना प्रभाव डालती है। अधिकतर सत्तर ऐसे हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत तीस से अधिक रहता है। कभी कांग्रेस का मजबूत आधार रहे ये मतदाता अब हवा के रुख के अनुसार अपना पाला बदल देते हैं। उनका मुस्लिम उद्देश्य हमेशा उन दलों को सत्ता से दूर रखना रहता है, जो हिंदू हितां की बात प्रस्तावित से करते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के कमजोर पड़ने के साथ मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को और रुख करने में जरा भी 'गुंज' नहीं किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की आँकड़ा मुस्लिम वोट मिले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी कुछ हिस्सा हासिल लगा। बीते निष्पक्ष चुनावों में यह पैटर्न बदला, जब मुस्लिम मतदाताओं ने एक दल के उम्मीदवार का चरण अपनी पसंद के पीछे नजर आने वाली पार्टी के पीछे छोड़ दिया। मुस्लिम लोग और नए प्रजापति के बाद पीडी एच जैसे पुराने सत्ता के बाद पीडी एच की उम्मीद उठाना काउंसिलर ने मैदान संभाला। 2022 के विधानसभा चुनाव में पीडी एच ने राष्ट्रीय उल्लास काउंसिलर के साथ गठबंधन कर कई विधायी उल्लास, लेकिन सफलता सीमित रही। इन प्रयासों से मुस्लिम वोटों में कुछ परिवर्तन तो हुआ, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। अब सबसे अधिक चिंता का विषय

है अखिलेश यादव की पार्टी का उभार। बिहार चुनावों में पांच सीटें जीतने के बाद अखिलेश ने उत्तर प्रदेश पर नज़रें टिका ली हैं। पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए सीटों पर लड़ने की घोषणा की थी और अब 2027 के चुनावों के लिए अखिलेश की पार्टी ने 200 क्षेत्रों को चार भागों में बांटकर चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर दी है। इसकी वजह भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल जिलों जैसे बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, संमल और बरेली में पार्टी का जनतावर बढ़ रहा है। निकाय चुनावों में यहां उसके रुख के अनुसार अपना पाला बदल देते हैं। उनका मुस्लिम उद्देश्य हमेशा उन दलों को सत्ता से दूर रखना रहता है, जो हिंदू हितां की बात प्रस्तावित से करते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के कमजोर पड़ने के साथ मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को और रुख करने में जरा भी 'गुंज' नहीं किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की आँकड़ा मुस्लिम वोट मिले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी कुछ हिस्सा हासिल लगा। बीते निष्पक्ष चुनावों में यह पैटर्न बदला, जब मुस्लिम मतदाताओं ने एक दल के उम्मीदवार का चरण अपनी पसंद के पीछे नजर आने वाली पार्टी के पीछे छोड़ दिया। मुस्लिम लोग और नए प्रजापति के बाद पीडी एच जैसे पुराने सत्ता के बाद पीडी एच की उम्मीद उठाना काउंसिलर ने मैदान संभाला। 2022 के विधानसभा चुनाव में पीडी एच ने राष्ट्रीय उल्लास काउंसिलर के साथ गठबंधन कर कई विधायी उल्लास, लेकिन सफलता सीमित रही। इन प्रयासों से मुस्लिम वोटों में कुछ परिवर्तन तो हुआ, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। अब सबसे अधिक चिंता का विषय

महाशिवरात्रि पर सुखा के कड़े इंतज़ान
संवाददाता-देवविश्व
महाशिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण, सुखी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन ने अपरा-
तैयारी पूरी कर ली है। 15 फरवरी को मनाए जाने वाले इस पर्व के जिले भर के प्रमुख इंतज़ाम मंदिरों पर सुखा के व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं। प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में भेषाचार पुलिस बल के साथ मिलकर की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। इसका पर्यवेक्षण ब्रह्मलुओं को किया जा रहा है। प्रशासन के प्रकाश की अनुविद्या से बघाना और कानून-उपन्याय के पूरी तरह निपटार में ब्रह्मा उपन्यास है।

फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी: सीएम मुख्यमंत्री बोले—नौकरी की गारंटी होगी विश्वविद्यालय की डिग्री



संवाददाता-गोरखपुर।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कैम्पियरगंज में बनने जा रहे प्रदेश के पहले बानिकी एवं उद्यान विद्यालय विश्वविद्यालय (फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी) की डिग्री नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी होगी। इस विश्वविद्यालय से डिग्री और डिप्लोमा लेकर निम्नलिखित वाले युवाओं के लिए देश और दुनिया में रोजगार के व्यापक अवसर होंगे। साथ ही यह विश्वविद्यालय अन्त्यादा किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सीएम योगी शनिवार को जंगल कौशलिया ब्लॉक में पुनर्निर्मित बीडीओ कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैम्पियरगंज में बने गिन्दावा जटायु संस्थान केन्द्र का उल्लेख करते हुए कहा कि कृताज्ञता जटायु करण हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है।

दिल्ली की बचां करते हुए कहा कि वहां डॉक्टर दमा रोगियों, बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह देते हैं। यह स्थिति पर्यवरण के साथ खिलवाड़ से बनती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास नीति है और दमघोड़ वातावरण से मुक्ति भी। इसी क्रम में कैम्पियरगंज में बनने जा रहा बानिकी विश्वविद्यालय पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने में और कारगर सिद्ध होगा। यह वनाच्छादन बढ़ाने और किसानों की आमदनी में वृद्धि का भी नया प्रयास होगा।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 के बाद प्रवेश और गोरखपुर के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि जब नौयात साफ हो तो परिणाम अपने आप आ जाते हैं। अच्छी दिशा में किए गए प्रयास से आज गोरखपुर में खाद कारखाना चालू हो चुका है। गोरखपुर में एम्स सेवाएं दे रहा है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज फिलिप्स का उल्लेख दे कर बन चुका है। गिरधारा में चीनी मिल दोबारा चालू हो गई है। गिन्दावा में कम्प्रेस्ड बायो गैस का प्लांट लाना चुका है। गीड़ा में उद्योगों की उद्योग नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर और प्रदेश में विकास के बहुत बड़े-बड़े योगदान हैं हैं। विकास की सोच ही वर्तमान और भी मजबूती के मध्य को उपजल बनाने में सहायक होगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंगल कौशलिया ब्लॉक के हर गांव से जुड़ाव का जिक्र किया। कहा कि वह वहां एक-एक

गांव गए हैं। हर गांव की समस्या जानते हैं, समस्या समाधान के लिए संघर्ष किया है। बाढ़ की स्थिति में पानी में घुसकर लोगों तक पहुंचे हैं। समस्याओं की तत्वीर पहचान से सामने भी तो लखनऊ से उन सभी समस्याओं का समाधान भी करा दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जंगल कौशलिया ब्लॉक के कैम्पियरगंज विमानस्थल क्षेत्र में आज विकास की जो स्थिति है, वह लोगों की कल्पनाओं से भी परे है। यहां कालेसर-जंगल कौशलिया बाईपास बन जाने से लोग सीधे लखनऊ पहुंच जाते हैं। वह भी सिर्फ ताँती-सांठे ताना घंटे में। विपटन से कुलीगंज क्षेत्र में सिर्फ आधा घंटा लगता है।

जंगल के हर प्रमुख सड़क फोरलेन में भी शहीदिया ब्लॉक के विकास की ताकत की। उन्होंने कहा कि जंगल कौशलिया के लोगों के साथ वह हमेशा खड़े हैं। विकास की हर मांग को वह पूरा करने के लिए तैयार हैं। सीएम योगी ने सभी लोगों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व शुभता का प्रतीक है। मुख्य कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंगल कौशलिया ब्लॉक परिसर में हुए पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही स्वर्गीय हारिका पांडेय शहीद स्मारक स्थल और पूर्व प्रमुख स्वर्गीय रामपति यादव की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने ब्लॉक परिसर में रुद्राक्ष का पीघरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

जमीनों पर कब्जा करने वाले विकास नहीं डिप्टी सीएम केशव का सपा पर जोरदार हमला

संवाददाता-अम्बेडकरनगर।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। कहा सपा अब समाप्त हो गई है। 2027 में सपा की वापसी का सपना पूरा नहीं होगा। 2047 तक प्रदेश में विपक्ष की वापसी नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को जिले के खजुरी में ग्राम चौपाल में शामिल हुए और स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित किया। साथ ही लामाथियों में आवास की चामी और चेक वितरित किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला।



उन्होंने कहा कि विपक्ष एक परिवार, एक क्षेत्र, एक जिले और एक समूह का विकास करता था। विकास के नाम पर लूट करता था। विकास कि जमीनों पर कब्जा करने वाले विकास नहीं कर सकते। कहा जब कैंड सरकार ने मनरेगा में गांधी के नाम पर हो रही लूट को बंद किया तो सभी को दर्द हो रहा है। विपक्ष का पीछीर का मतलब परिवार डबलमेंट एजेंसी है।

कुमार को प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम से मीडिया ने पूछा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं केंद्र और प्रदेश सरकार में जंग छिड़ी है, अब क्या बुलंदगढ़ का जंगल हटाया भेजेगे। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देखिए अखिलेश यादव बहुत अवसाद और सताव में हैं। बिहार में होतस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने गए थे लेकिन बड़ी मुश्किल

थाने पुलिस नहीं गुंडे चलाते

सैनिक सम्मेलन, अपराध अधीक्षक ने दिए अपराध

संवाददाता-संतकबीरनगर।

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में सैनिक सम्मेलन और मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान अपराध निवारण और लवित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह भी इस बैठक में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत सैनिक सम्मेलन से हुई, जिसमें जनपद के सभी थानों और शाखाओं से आए पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुना गया। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निर्देशित किया। मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान यातायात माह, साइबर अपराध और महिला अपराध जैसे विभिन्न अभियानों की संक्षिप्त की गई। जनपद में घटित अपराधों की घटनाओं, पंजीकृत अभियोगों और लवित विवेचनाओं की गहन समीक्षा करते हुए उनके कारण-दोष के आधार पर समग्रबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, वांछित अभियुक्तों

बीएसए ग्राउंड में 267 जोड़ों का सामूहिक विवाह: डीएम

संवाददाता-सिद्धार्थनगर।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शनिवार को बीएसए ग्राउंड में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 267 जोड़ों विवाह बंधन में बंधे। कार्यक्रम में दुर्गारियागंज सांवाद जयप्रकाश पांडे, कमिश्नर विद्याचरण श्यामसुंदरी जी, जिलाधिकारी शिवशरणया जीपन और पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव महाजन सहित कई जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

कुल 358 पंजीकृत जोड़ों में से 267 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ। इनमें 195 हिंदू, 55 बौद्ध और 31 मुस्लिम जोड़ों शामिल थे। मुस्लिम संवाददाता के शांति का निहाल हुआ, जबकि 15 जोड़ों अनुप्रस्थित गए। सभी विवाह उनके संबंधित 6 तासिक रीति-रिवाजों के अनुसार सम्पन्न किए गए। हिंदू जोड़ों का विवाह बौद्ध मंत्रोच्चारण से, मुस्लिम जोड़ों का विवाह मौलाना द्वारा और बौद्ध अनुयायियों का विवाह उनकी परंपरा

संवाददाता-सिद्धार्थनगर।



के अनुसार हुआ। इस आयोजन में नौवाद, बंदरूप, उरका बाजार, लोटन, जोगिया, होलतनगर और बंदनी विकास जैसे के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्रों के जोड़ों भी शामिल हुए।

जिलाधिकारी शिवशरणया जीपन के नेतृत्व में कार्यक्रम सुचारुवर्धित रूप से सम्पन्न हुआ। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं की निगरानी की, ताकि नवविवाहित जोड़ों और उनके परिवारों को कोई अड़बुलना न हो।

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक क्यू के बैंक खाते में डीबीटी के मा

सामुदायिक श्रैणिक पलोर निर्माण के लिए आवेदन शुरू

संवाददाता-सिद्धार्थनगर।

जिले में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सशक्त बनाने और किसानों को बेहतर मर्हत्त सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि विभाग ने सामुदायिक श्रैणिक पलोर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण निशान योजना के तहत एफपीओ 15 करारी की एक सप्ताह तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उप कृषि निदेशक राधेश कुमार ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य दलहन फसलों की समय पर मर्हत्त सुनिश्चित करना है। इससे किसानों को खुद और खुशिक्ष स्थान पर फसल की मर्हत्त करने की सुविधा मिलेगी, जिससे फसल की गुणवत्ता नहीं रहेगी और नुकसान की संभावना कम होगी। एफपीओ के माध्यम से सामुदायिक पलोर पर डर श्रेष्ठिस्त पलोर का निर्माण कराया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक किसान इस्का लाभ उठा सकें। योजना के तहत श्रेष्ठिस्त पलोर का निर्माण 20 करोड़ लंबा और 10 मीटर चौड़ा अघातकार या 8 मीटर अर्धवृत्ताकार के गोलाकार आकार में किया जाएगा। इस जमीन की सहाय से एक फीट ऊंचाई पर बनाया जाएगा, ताकि बारिश या नमी से फसल प्रभावित न हो। एक श्रेष्ठिस्त पलोर के निर्माण की कुल लागत 1.70 लाख रुपये निर्धारित राशि है। इसमें से 50 प्रतिशत राशि संबंधित एफपीओ को बहन करनी होगी, जबकि शेष 50 प्रतिशत यातायात इस्का 85 हजार रुपये का अनुदान कृषि विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। आवेदन के समय एफपीओ को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और 2500 रुपये की जमानत धनराशि जमा करनी होगी। चयन प्रक्रिया ई-लॉटरी के माध्यम से की जाएगी।

जगदंबिका पाल बोले— स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अनैतिक



जिले में पहुंचे दुर्गारियागंज के सांवाद और वरिष्ठ भाजपा नेता जगदंबिका पाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सदन में अमर्यादित अवसर कर रहे हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह से अमान्य और गलत कदम बताया।

सांसद पाल ने यह भी कहा कि राहुल गांधी सदन में बेवृत्तिवादी आरोप लगाते हैं उनका भी माथा एक सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं होगा। उन्होंने दिग्गजी की भारत में सभी को स्वतंत्रता है, लेकिन राहुल गांधी इस लोकतांत्रिक आजादी का दुरुपयोग कर रहे हैं।

गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज कराएं एफआईआर —सीएम योगी



संवाददाता-गोरखपुर।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी मामले में जांच के दौरान यदि गलत रिपोर्ट लंबाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। हर मामले का निष्पक्ष जांच करके ही उसका निस्तारण होना चाहिए। किसी भी प्रकरण में लापरवाही या शिथिलता अमर्य होगी। सीएम योगी ने शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए ये निर्देश प्रशासन व पुलिस के अधिकारों को दिए। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्वमित भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। सीएम योगी ने सभी को आश्वास

साधना में अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसका पता लगाकर निस्तारण कराया जाए और किसी स्तर पर जानबूझकर कर प्रकरण को लवित रखा गया है तो संबंधित के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधि सम्मत कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया। हर बार की तरह इस बार भी जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जल से जुद्ध अस्पताल के इस्टेमेंट की प्रक्रिया पूरी करकर शासन को उपलब्ध करा दें। इलाके के लिए मुख्यमंत्री विकास निा कोष से पर्याप्त मदद की जाएगी। जब्त जमीन में परजिनने के साथ और बन्ना को थारू-दुलाकर सीएम योगी ने उन्हें बोलकट दिया और कुछ पढ़ने के लिए प्रेरित किया। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान शनिवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। गुरु गोपाल का दर्शन पूजन करने तथा अपने गुरुदेव ब्रह्मली महंत अर्चनाधारा की प्रतिमा समक्ष शीश झुकाने के बाद वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले। मंदिर की गोपाला में पहुंचकर उन्होंने गोसेवा की। गायों और गंधक को स्नेहित भाव से अपने हाथों से गुड़ खिलाया।

संवाददाता-गोरखपुर।

अखंड हिंद फौज एवं राष्ट्र वंदन समिति के संस्कृत तत्वानाम में शनिवार को पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर शहीद जवानों के सम्मान में 'श्रद्धांजलि' चरुचर 'शहीद सम्मान यात्रा' निकली गई। कार्यक्रम में 14 फरवरी, 2019 को राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण खोछावर करने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 वीर जवानों को याद किया और उनकी वीरता को नमन किया। श्रद्धांजलि सभी की शुरुआत अमर शहीदों के चित्रों के समूह 50 विरा प्रखलित कर पुष्प अर्पित कर और दो मिनट का मौन खीर करी गई। इस दौरान पूर्व माहिल दैर्मासिक के नारों और शहीद जवान अमर रहें के उद्घोष से गुजारागमन रहा।

संवाददाता-गोरखपुर।

विजय खेमका एवं डॉ शशि भूषण शर्मा, मेजर नित्यनंद सिवारि, सुब्रह्म मेजर अरवनी पाठक ने हर्षा डीर दिखारक यात्रा प्रारंभ की। यह यात्रा विश्वविद्यालय पार्क से छात्र संघ बौराहा, आंबेडकर चौराहा, कचहर चौक होते हुए विश्वविद्यालय पार्क पहुंची। इस अवसर पर अतिथियों ने सभी को संबोधित किया। अखंड हिंद फौज के डीसीओ अश्व अग्रहार ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को हमारे सुखा बलों के साहस और समर्पण से अवगत करना था। उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से राष्ट्र की सुरक्षा और एकता के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन दुर्गा श्रिवादी ने किया। कार्यक्रम में एमएचएल सीनियर अश्व, अनमोल, शुभम, आलोक, शोभित, श्रेष्ठा, प्रमैला, शाना जयसवाल, स्वीटी देवीलाल आदि मौजूद रहे।

पिता ने नशेड़ी बेटे के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा

संवाददाता-गोरखपुर।

कैम्पियरगंज क्षेत्र के कोठिया बुजुर्ग गांव निवासी एक पिता ने अपने नशेड़ी बेटे के खिलाफ अपादिन आरोपों और धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनौरा बुजुर्ग गांव के रहने वाले पंचम कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका पुत्र श्रीकांत जाड़ा, शराब सेहत अमर्य मादक पदार्थों का सेवन करता है और नशे की हालत में अपादिन आरोपों के सदस्यों के साथ मारपीट करता है। आरोप है कि उसने पंचम कुमार को मारकर उनका शिर फोड़ दिया, इसके बाद वह सिर में टाका लगाकर थाने पहुंचे। पीडित का यह भी आरोप है कि कुछ दिन पूर्व आरोपी ने उनका मोबाइल फोन तोड़ दिया था। वह नशा करने के लिए अपादिन पैसे की मांग करता है और न देने पर जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राथिनी श्रीमती रूपा गौरी गुप्ता कुमर उपप्राध्याय महास्वा शिवपुरी कालोनी शास्त्रीनगर जनपद और नशे की हालत में अपादिन आरोपों के सदस्यों के साथ मारपीट करता है। आरोप है कि उसने पंचम कुमार को मारकर उनका शिर फोड़ दिया, इसके बाद वह सिर में टाका लगाकर थाने पहुंचे। पीडित का यह भी आरोप है कि कुछ दिन पूर्व आरोपी ने उनका मोबाइल फोन तोड़ दिया था। वह नशा करने के लिए अपादिन पैसे की मांग करता है और न देने पर जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

दैनिक

भारतीय बस्ती

संस्थापक समादक स्व.

रविश चन्द्र पाण्डेय

प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा रचण

प्रिण्टिंग प्रेस वि०. नया हाल

1-4 A लोडिया कामप्लेक्स

जिला पंचायत भवन गान्धीनगर

बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं

प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक-दिनेश सिंह

संयुक्त सम्पादक-प्रदीप पाण्डेय

अयोध्या-कैलाश चन्द्र पाण्डेय

वृत्तुकी मंदिर विस्तार लक्ष्मण

अयोध्या-कैलाश

लखनऊ कार्यालय-

अखिलारा चौकाल, एल.ई.ए. कालोनी,

शेखर चणू कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय-

गोष्ठी गोरखपुर।

मो 9336715406, 8400925463

ईमेल bhartiyaabasti@gmail.com